राम रतन *उर्फ* रतन अहीर और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य

22 सितंबर, 1964

(ए. के. सरकार, के. एन. वांचू और रघुबर दयाल, न्यायमूर्तिगण)

पशु अतिक्रमण अधिनियम, (1871 का अधिनियम 1) धारा 10- फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले पशु- कानून के तहत ज़ब्ती- ज़ब्ती उचित नहीं- क्या यह चोरी के बराबर है- क्या स्वामी संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का हवाला देते हुए पशुओं को छुड़ा सकता है- भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45), धारा 97, 378।

अपीलकर्ताओं ने उस खेत से मवेशी ज़ब्त कर लिए, जिस पर उनका दावा था कि वे उनके कब्ज़े में हैं। वे मवेशी बाड़े में ले जा रहे थे और ऐसा वे पशु अतिक्रमण अधिनियम, 1871 की धारा 10 के तहत कर रहे थे। शिकायतकर्ताओं, जिनके मवेशी थे, ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की और इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए और शिकायतकर्ता पक्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। सत्र न्यायाधीश ने पाया कि मवेशियों को अवैध रूप से ज़ब्त किया गया था क्योंकि जिस खेत से उन्हें लिया गया था वह शिकायतकर्ताओं का था। हालांकि, उन्होंने अपीलकर्ताओं को इस आधार पर बरी कर दिया कि उन्हें शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार था, जबकि शिकायतकर्ताओं को अपने मवेशियों को बलपूर्वक छुड़ाने का अधिकार नहीं था। बरी किए जाने के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ताओं को संपत्ति की रक्षा का अधिकार था और वे बलपूर्वक मवेशियों को छुड़ा सकते थे। इस निष्कर्ष के आधार पर उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया, जिसके बाद अपीलकर्ता विशेष अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय में आए।

विचारणीय मुख्य प्रश्न यह था कि क्या कोई व्यक्ति जो पशु अतिक्रमण अधिनियम, 1871 की धारा 10 के तहत कार्य करने का दावा करते हुए अवैध रूप से मवेशियों को जब्त

करता है, चोरी या डकैती का अपराध करता है या नहीं, क्योंकि इस पर निर्भर करेगा कि किस पक्ष को आत्मरक्षा का अधिकार है।

अभिनिर्धारित किया: (i) जब कोई व्यक्ति इस आधार पर मवेशियों को जब्त करता है कि वे उसकी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे और उसकी फसल या उपज को नुकसान पहुंचा रहे थे और यह बताता है कि वह उन्हें पशुशाला ले जा रहा है, तो वह चोरी का कोई अपराध नहीं करता है, चाहे वह उस भूमि या फसल पर अपने अधिकार के बारे में कितना भी गलत क्यों न हो।[305 बी]

क्वीन बनाम प्रीओनाथ बनर्जी, 5 *डब्ल्यू.आर.* 68 *(आपराधिक), वाजुद्दीन बनाम रहीमुद्दीन,* (1917) 18 *आपराधिक एल.जे.* 849, *अब्दुल खालिक बनाम एम्परर, ए.आई.आर.* 1941 *लाह* 221, *परयाग राय बनाम आरजू मियां, आई.एल.आर.* 22 *कैल.* 139 *और क्वीन इम्प्रेस बनाम श्री चूरन चुंगो, आई.एल.आर.* 22 *कैल.* 1017, अनुपयुक्त ठहराया गया।

एम्प्रेस बनाम रामजियावान, (1881) 1 ऑल. डब्ल्यू.एन. 158 और *दयाल बनाम एम्परर,* ए.एल.आर. 1943 अवध 280, अनुमोदित।

(ii) मात्र पशुओं को जब्त करना चोरी नहीं है। चोरी के लिए चुराए गए पशुओं का बेईमानी से आवागमन भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले पशुओं को जब्त करके उन्हें पशु बाड़े में ले जाता है, वह अधिनियम की धारा 10 में दिए गए विशिष्ट निर्देश के अनुसार ऐसा करता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होने के कारण उसके इस कार्य को प्रथम दृष्टया बेईमानी नहीं माना जा सकता। न ही पशुओं के स्वामी को अनुचित हानि पहुँचाने या स्वयं को अनुचित लाभ पहुँचाने का इरादा उस पर तब तक आरोपित किया जा सकता है जब तक कि पशुओं को पशु बाड़े में ले जाने का उसका घोषित इरादा किसी अन्य इरादे को छुपाने का बहाना न हो, जिसका अनुमान परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। वास्तव में, पशुओं को जब्त करने से किसी भी पक्ष को कोई अनुचित लाभ या अनुचित हानि नहीं होती है।[303 बी-ई; 304 ई-एच]

के. एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य [1957] एस.सी.आर. 623, पर अवलम्बन किया गया।

(iii) अधिनियम की धारा 10 के तहत जब्त किए गए पशुओं के स्वामी का उपाय अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्रवाई करना है। उसे जब्त किए गए पशुओं को छुड़ाने के लिए बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। शिकायतकर्ता जो तेज धार वाले हथियारों और *लाठियों* से लैस होकर पशुओं को छुड़ाने गए थे, उन्हें अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपनी संपत्ति की रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं था।[305 बी-सी]

(iv) इन परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं को यह उचित रूप से आशंका थी कि शिकायतकर्ता अपने मवेशियों को बचाने के उद्देश्य से उन्हें गंभीर चोट पहुँचाएँगे, इसलिए उन्हें आत्मरक्षा का अधिकार था और उन्होंने दूसरे पक्ष को चोट पहुँचाने और उसके एक सदस्य की मृत्यु करने में कोई अपराध नहीं किया।[306 एफ- जी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: वर्ष 1963 की आपराधिक अपील संख्या 29

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 13 दिसंबर, 1962 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील, सरकारी अपील संख्या 24/1960।

अपीलकर्ताओं की ओर से *नूरुद्दीन अहमद, बी.पी. सिंह और यू.पी. सिंह* उपस्थित हुए।

उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से *बी.पी. झा* ।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा सुनाया गया

रघुबर दयाल, न्यायमूर्ति। विशेष अनुमति से दायर इस अपील में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या कोई व्यक्ति जो पशु अतिक्रमण अधिनियम, 1871 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 के तहत अवैध रूप से पशुओं को जब्त करता है, चोरी या डकैती का अपराध करता है या नहीं। प्रश्न इस प्रकार उठता है।

28 नवंबर, 1957 की सुबह, रामनंदन सिंह और राम रतन *उर्फ* रतन अहीर समेत कई लोगों ने शमनारायण सिंह समेत कई व्यक्तियों के मवेशियों को एक *कुर्थी* के खेत में चरते

हुए देखा। इस खेत को लेकर बुनियादी विद्यालय के अधिकारियों और शमनारायण सिंह के बीच विवाद था, और दोनों ही इस पर अपना दावा कर रहे थे। रामनंदन सिंह और अन्य लोगों ने उन मवेशियों को ज़ब्त कर लिया और उन्हें तिलौथु गांव के पशु बाड़े में ले जाने लगे। ये लोग धारदार हथियारों और *लाठियों* से लैस थे।

मवेशियों को जब्त किए जाने की खबर शमनारायण सिंह और गांव के अन्य लोगों तक पहुंची। कई लोग, अलग-अलग हथियारों से लैस होकर, मवेशियों को छुड़ाने के लिए गांव से निकले। रास्ते में और लोग उनसे जुड़ गए। सुखरी महतो, देवचरण, शेओदत्त, हरि महतो और रामदेव समेत इस दल ने मवेशी बाड़े से कुछ दूरी पर दूसरे दल को पकड़ लिया और उनसे मवेशियों को छोड़ने को कहा। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर वे आपस में भिड़ गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ताओं के दल के सदस्यों ने शमनारायण सिंह और उनके साथियों पर हमला किया। अपीलकर्ताओं का कहना है कि उन पर हमला दूसरे दल ने किया था। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप शमनारायण सिंह की तरफ से पांच लोग घायल हो गए। इनमें से रामदेव को भाले से दाहिनी जांघ में गहरा घाव लगा। इसी चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सुखारी महतो को 4 चीरे सहित 16 चोटें आईं। अन्य तीन घायलों को मामूली चोटें लगीं। देवचरण को खरोंच आई, शेओदत्त सिंह को छिद्रयुक्त घाव, सूजन और खरोंच आई, और हरि महतो को छिद्रयुक्त घाव लगा। अपीलकर्ताओं की ओर से चार लोग घायल हुए। रामनंदन सिंह को 4 चीरे और 3 छिद्रयुक्त घावों सहित 12 चोटें आईं। रतन और अहीर को 2 छिद्रयुक्त घावों सहित तीन चोटें आईं। शेओरतन को 2 छिद्रयुक्त घावों सहित 5 चोटें आईं। राजकुमार सिंह को एक छिद्रयुक्त घाव सहित 2 चोटें आईं।

दोनों पक्षों की ओर से थाना में प्रतिवेदन दर्ज कराई गई। हरि महतो ने शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से 20 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिवेदन दर्ज कराई। रतन अहीर ने 26 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिवेदन दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के परिणामस्वरूप 28 व्यक्तियों को मुकदमे के लिए भेजा। आरा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन सभी को बरी कर दिया। उन्होंने पाया

कि (1) घटना की तिथि को शमनारायण सिंह विवादित *कुर्थी* खेत पर वैध कब्जे में थे और बचाव पक्ष की ओर से उठाया गया दावा सद्भावनापूर्ण नहीं था; (2) *चरवाहों* के विरोध के बावजूद उनकी उपस्थिति में मवेशियों को जब्त किया गया था। (3) यद्यपि इन परिस्थितियों में अभियुक्त पक्ष द्वारा *कुर्थी* के खेत से मवेशियों को जब्त करना एक गैरकानूनी कृत्य था, फिर भी शिकायतकर्ता पक्ष, जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, द्वारा मवेशियों को छुड़ाने के लिए उनका पीछा करना उचित नहीं था, क्योंकि इससे उनके द्वारा बल प्रयोग करके अपने मवेशियों को छुड़ाने का दृढ़ संकल्प प्रदर्शित होता है और इसलिए मवेशियों के मालिकों को उन लोगों के हाथों से अपने मवेशियों को छुड़ाने का कोई अधिकार नहीं था जिन्होंने पहले बल प्रयोग करके उन्हें जब्त किया था; (4) इस दृष्टिकोण के पक्ष में प्रबल संभावना थी कि अभियोजन पक्ष ने ही संकट उत्पन्न किया और आक्रमण शुरू करने के लिए आक्रामकता दिखाई तथा घटना स्थल पर हमले की शुरुआत के तरीके के बारे में अभियोजन पक्ष का विवरण उसे स्वीकार्य नहीं था तथा अभियोजन पक्ष की कहानी का कुछ हिस्सा महत्वपूर्ण रूप से छिपाया गया प्रतीत होता था तथा इन परिस्थितियों में, आरोपी पक्ष को अभियोजन पक्ष के हाथों गंभीर चोट या मृत्यु का उचित भय था तथा अभियोजन पक्ष के लोगों को ऐसी चोटें पहुँचाने में वे अपने शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में न्यायसंगत थे जिससे मृत्यु हो सकती थी, इस प्रकार हुई मृत्यु न्यायोचित हत्या थी।

बिहार राज्य ने 28 आरोपियों के बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 13 आरोपियों के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए रतन अहीर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत तथा अन्य आरोपियों को धारा 326 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत तथा कुछ अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया। यह उल्लेखनीय है कि एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी और 14 अन्य को बरी कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश से सहमति जताते हुए कहा कि विवादित भूखंड शमनारायण सिंह के कब्जे में था और आरोपियों द्वारा मवेशियों को जब्त करना अवैध

था। हालांकि, विद्वान न्यायाधीशों का मत था कि सत्र न्यायाधीश ने कानून की गलत व्याख्या की थी, यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष के सदस्य केवल इसलिए बलपूर्वक मवेशियों को छुड़ाने के हकदार नहीं थे क्योंकि आरोपी मवेशियों को कुछ दूरी तक ले जाने में सफल हो गए थे। उन्होंने यह तर्क दिया कि एक बार जब मवेशियों की ज़ब्ती अवैध पाई जाती है, तो आरोपी पक्ष के सदस्य चोरों की स्थिति में होते हैं न कि डकैतों की - क्योंकि उन्होंने चरवाहों पर बल प्रयोग करके मवेशियों को छीन लिया था, और इसलिए अभियोजन पक्ष के सदस्यों को संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार है और वे बल प्रयोग करके अपने मवेशियों को वापस पा सकते हैं, इस शर्त के साथ कि आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग न किया जाए। यह भी पाया गया कि अभियोजन पक्ष ने मवेशियों को बचाने के प्रयास में अभियुक्तों के पक्ष द्वारा हिंसक हमला किया था। विद्वान न्यायाधीश संभवतः सत्र न्यायाधीश के इस मत से सहमत नहीं थे कि हमला अभियोजन पक्ष द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि इस मत के समर्थन में अभिलेख पर कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन्होंने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा हमला शुरू करने से भी बचाव पक्ष को कोई औचित्य नहीं मिलता, क्योंकि मवेशियों को बचाने के कार्य में बचाव पक्ष को आत्मरक्षा करना अनिवार्य था। इस अपील में उठाए गए कानून के प्रश्न पर विचार करने के लिए, हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं कि विवादित भूखंड शमनारायण सिंह के कब्जे में था, कि अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों ने उस भूखंड में चर रहे मवेशियों को यह आरोप लगाते हुए जब्त कर लिया कि वे उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे और वे उन्हें पशुशाला ले जाएंगे, कि शमनारायण सिंह और अन्य सशस्त्र लोग मवेशियों को छुड़ाने गए और आरोपी पक्ष से मिलने पर उन्होंने उनसे मवेशियों को छोड़ने के लिए कहा और कुछ कहासुनी के बाद आरोपी पक्ष ने हमला शुरू कर दिया।

इस बात में कोई विवाद नहीं है—और दोनों पक्षों द्वारा दर्ज की गई प्रतिवेदनों में शुरू से ही यह आरोप लगाया गया है—कि अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों ने मवेशियों को इस आधार पर जब्त किया था कि वे उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इससे यह स्पष्ट

होता है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के तहत मवेशियों को जब्त करने का प्रयास किया। इस तथ्य को देखते हुए कि भूखंड शमनारायण सिंह के कब्जे में था और उन्होंने ही फसल उगाई थी, ऐसी जब्ती अवैध थी। अतः प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार मवेशियों को जब्त करके अपीलकर्ताओं ने चोरी का अपराध किया? इस बिंदु का निर्धारण करना आवश्यक है क्योंकि मवेशियों को जब्त करके अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा चोरी का अपराध किए जाने पर ही शमनारायण सिंह और उनके साथियों को, जो मवेशियों को बचाने गए थे, संपत्ति की रक्षा का कोई अधिकार प्राप्त होता है। यदि अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों का कृत्य चोरी की श्रेणी में नहीं आता, तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और इसलिए शमनारायण सिंह और अन्य लोगों को संपत्ति की रक्षा का कोई अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में परिभाषित "अपराध" के विरुद्ध उत्पन्न होता है, अर्थात् ऐसा कृत्य जो संहिता द्वारा दंडनीय हो। यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा कोई अन्य अपराध नहीं किया गया है, जिसके कारण शमनारायण सिंह और अन्य लोगों को संपत्ति की रक्षा का अधिकार प्राप्त होता।

उठाए गए प्रश्न का निर्धारण करने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ लेना उचित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपीलकर्ताओं के कौन से कार्य इसके प्रावधानों के अनुरूप होंगे, कौन से उनके विरुद्ध होंगे और यदि वे ऐसे प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वे किस प्रकार उत्तरदायी होंगे। धारा 10 किसी भूमि पर उगाई गई फसलों में हित रखने वाले कुछ व्यक्तियों को उस भूमि पर अतिक्रमण करने वाले और उस भूमि या उस पर उगी किसी फसल या उपज को नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं को जब्त करने या जब्त करवाने का अधिकार देती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जब्त किए गए पशुओं को 24 घंटे के भीतर उस गांव के लिए स्थापित पशु बाड़े में भेजा जाए जहां वह भूमि स्थित है। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि सभी पुलिस अधिकारी, आवश्यकता पड़ने पर, ऐसी जब्ती का विरोध रोकने और ऐसी जब्ती करने वाले व्यक्तियों से उन्हें छुड़ाने में सहायता करेंगे।

धारा 11 कुछ व्यक्तियों को सार्वजनिक सड़कों, नहरों, तटबंधों और उस धारा में उल्लिखित अन्य चीजों को नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं को जब्त करने का अधिकार देती है। धारा 12 जब्त किए गए प्रत्येक पशु पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है।

अध्याय V अवैध ज़ब्ती या हिरासत की शिकायतों से संबंधित है और इसमें चार खंड हैं, धारा 20 से 23 तक। धारा 20 इस प्रकार है:

> *शिकायत करने का अधिकार।* कोई भी व्यक्ति जिसके पशुओं को इस अधिनियम के तहत जब्त किया गया है, या इस प्रकार जब्त किए जाने के बाद इस अधिनियम के उल्लंघन में हिरासत में रखा गया है, वह जब्ती की तारीख से दस दिनों के भीतर किसी भी समय जिले के दंडाधिकारी या जिले के दंडाधिकारी के संदर्भ के बिना आरोपों को प्राप्त करने और उन पर सुनवाई करने के लिए अधिकृत किसी भी दंडाधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकता है।

धारा 21 ऐसी शिकायत पर प्रक्रिया से संबंधित है और धारा 22 में लिखा है:

> "*अवैध ज़ब्ती या हिरासत के लिए मुआवज़ा।* यदि ज़ब्ती या हिरासत को अवैध घोषित किया जाता है, तो दंडाधिकारी शिकायतकर्ता को ज़ब्ती या हिरासत से हुई हानि के लिए उचित मुआवज़ा देगा, जो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा। यह मुआवज़ा ज़ब्ती करने वाले या पशुओं को हिरासत में रखने वाले व्यक्ति द्वारा, पशुओं की रिहाई के लिए शिकायतकर्ता द्वारा अदा किए गए सभी जुर्माने और खर्चों सहित अदा किया जाएगा।"
>
> *पशुओं की रिहाई।* और, यदि पशुओं को रिहा नहीं किया गया है, तो दंडाधिकारी, ऐसे मुआवजे के अलावा, उनकी रिहाई का आदेश देगा और यह निर्देश देगा कि इस अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने और खर्च

उस व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाएं जिसने पशुओं को जब्त किया या हिरासत में लिया।"

धारा 23 में प्रावधान है कि धारा 22 में उल्लिखित मुआवजा और व्यय इस प्रकार वसूल किए जा सकते हैं जैसे कि वे दंडाधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने हों।

धारा 24 अधिनियम के तहत जब्त किए जाने योग्य पशुओं की जब्ती का बलपूर्वक विरोध करने या जब्ती के बाद ऐसे पशुओं को पशु बाड़े से या उन्हें पशु बाड़े में ले जा रहे या ले जाने वाले किसी व्यक्ति से छुड़ाने पर दंड का प्रावधान करती है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम छह महीने की कैद या पांच सौ रुपये का जुर्माना हो सकता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत पशुओं की अवैध ज़ब्ती को अपराध नहीं माना गया है। पशुओं को अवैध रूप से ज़ब्त करने वाले व्यक्ति को पशु स्वामी को हुई हानि के लिए मुआवज़ा देना होगा, चाहे वह अवैध ज़ब्ती के कारण हो या अधिनियम के उल्लंघन में पशुओं को हिरासत में रखने के कारण। उसे पशुओं को छुड़ाने में लगे जुर्माने और खर्चों का भुगतान भी करना होगा। धारा 20 में प्रयुक्त "इस अधिनियम के अंतर्गत" का अर्थ "अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार" नहीं है, बल्कि "अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतीत होने वाला" है, क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत "ज़ब्ती", अर्थात् "अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ज़ब्ती", कभी भी अवैध नहीं हो सकती। धारा 20 अवैध ज़ब्ती या हिरासत की शिकायतों से संबंधित है। धारा 24 में प्रयुक्त शब्द भिन्न हैं और अधिनियम के अंतर्गत ज़ब्त किए जाने योग्य पशुओं की ज़ब्ती का बलपूर्वक विरोध करना दंडनीय है। यदि पशु ज़ब्त किए जाने योग्य नहीं थे, तो उनकी ज़ब्ती का बलपूर्वक विरोध करना धारा 24 के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 25 पशुओं को अतिक्रमण कराने से होने वाले नुकसान के लिए जुर्माने की वसूली का तरीका बताती है। इस प्रकार, यह दंड संहिता के तहत उस अपराध को ध्यान में रखती है जो पशुओं को दूसरों की भूमि पर अतिक्रमण कराने वाले व्यक्ति द्वारा

किया जाता है, और यह प्रावधान करती है कि उस अपराध के लिए लगाया गया कोई भी जुर्माना उन सभी या किसी भी पशुओं की बिक्री से वसूल किया जा सकता है जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था, चाहे वे पशु अतिक्रमण करते समय जब्त किए गए हों या नहीं और चाहे वे अपराध के दोषी व्यक्ति की संपत्ति हों या अतिक्रमण करते समय केवल उसके संरक्षण में हों।

धारा 26, *अन्य बातों के अलावा*, सूअरों द्वारा उपेक्षा या किसी अन्य कारण से फसलों आदि या सार्वजनिक सड़कों को हुए नुकसान के लिए दंड का प्रावधान करती है, या यदि राज्य सरकार ऐसा अधिसूचित करती है तो मवेशियों द्वारा सामान्यतः हुए नुकसान के लिए दंड का प्रावधान करती है।

धारा 29 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिबंधित करता हो जिसकी फसल या भूमि की अन्य उपज को पशुओं के अतिक्रमण से नुकसान पहुंचा हो, उसे किसी सक्षम न्यायालय में मुआवजे के लिए मुकदमा करने से रोकता हो। धारा 30 में यह प्रावधान है कि अधिनियम के तहत दोषी ठहराने वाले दंडाधिकारी के आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया गया कोई भी मुआवजा, ऐसे मुकदमे में मुआवजे के रूप में दावा की गई या उसे प्रदान की गई किसी भी राशि से समायोजित और घटाया जाएगा। अधिनियम में ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है जिसकी फसल या भूमि की अन्य उपज पशुओं के अतिक्रमण से क्षतिग्रस्त हो गई हो। इसलिए, धारा 30 ऐसे व्यक्ति को धारा 545 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मुआवजे के प्रावधान को संदर्भित करती प्रतीत होती है, उस दंडाधिकारी द्वारा जो उस व्यक्ति को दोषी ठहराता है जिसके पशुओं ने नुकसान पहुंचाया था, दंड संहिता के तहत उपद्रव के अपराध या अधिनियम की धारा 24 और 26 के तहत अपराधों के लिए।

इस अधिनियम में धारा 29 और 30 के प्रावधानों के समान कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि जिस व्यक्ति के पशुओं को अवैध रूप से जब्त या हिरासत में

लिया गया है, वह सक्षम न्यायालय में मुआवजे के लिए मुकदमा कर सकता है और अधिनियम की धारा 22 के तहत दंडाधिकारी द्वारा दिया गया मुआवजा ऐसी कार्यवाही में उसे दी गई किसी भी राशि से काटा जाएगा। अधिनियम पशुओं की अवैध जब्ती या हिरासत को अपराध नहीं बनाता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का इरादा था कि अधिनियम के अध्याय V के प्रावधान मवेशियों की अवैध ज़ब्ती या हिरासत के मामले से व्यापक रूप से निपटेंगे और जिस व्यक्ति के मवेशियों को इस प्रकार ज़ब्त या हिरासत में लिया गया है, उसे अधिनियम की धारा 22 के तहत ही उपाय उपलब्ध होगा, कोई अन्य नहीं, और मवेशियों की अवैध ज़ब्ती या हिरासत दंड संहिता के तहत कोई अपराध नहीं होगा। इसके पीछे ठोस कारण प्रतीत होता है, क्योंकि अधिनियम का उद्देश्य फसलों और भूमि की अन्य उपज को मवेशियों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण से होने वाली क्षति से बचाना और भूमि के कृषकों और कब्जेदारो को इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि और चोट से बचाना था।

पशुओं द्वारा अतिक्रमण से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए 1871 का पशु अतिक्रमण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। पहला पशु अतिक्रमण अधिनियम 1857 का अधिनियम III था और इसकी प्रस्तावना में लिखा है:

> "जबकि किसानों और भूमि के कब्जेदार पशुओं द्वारा फसलों और अन्य उपज को होने वाले नुकसान से हानि और क्षति झेलते हैं; और जबकि पशुओं द्वारा सार्वजनिक सड़कों और तटबंधों के किनारों और ढलानों को नुकसान पहुंचाया जाता है; जबकि पशुओं द्वारा उन पर अतिक्रमण करने से नुकसान होता है; और जबकि उपर्युक्त नुकसान करने वाले पशुओं को पकड़ने और हिरासत में लेने का अधिकार देना और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भटकते हुए पाए जाने वाले पशुओं के निपटान के लिए प्रावधान करना आवश्यक है: इसलिए यह निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है:"

सन् 1857 के अधिनियम की धारा II के तहत किसी भी भूमि के कृषक या कब्जेदार को यह अधिकार दिया गया था कि वह अपनी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले और उस पर उगी फसल या उपज को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी पशु को जब्त कर सकता है या जब्त करवा सकता है। अधिनियम की धारा 10 ने अन्य व्यक्तियों को भी यही अधिकार दिया था। हालांकि, इसने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं को जब्त करने का अधिकार उन सभी को नहीं दिया था जो उन्हें फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए देख सकते थे। यद्यपि किसी व्यक्ति की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले पशुओं को जब्त करने का अधिकार केवल तभी दिया गया था जब पशु भूमि या उस पर उगी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हों, फिर भी पशुओं को जब्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के लिए यह निर्धारित करना एक कठिन मामला माना जाना चाहिए था कि क्या पशुओं ने उसकी भूमि या फसल को नुकसान पहुंचाया है और उसके बाद ही उन्हें जब्त किया जाए। अधिकृत व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सबसे पहले अपनी भूमि पर मौजूद मवेशियों को जब्त करेगा, यह मानते हुए कि उन्होंने फसल या भूमि को नुकसान पहुंचाया होगा और मवेशियों को जब्त किए बिना खेत में उनकी उपस्थिति से और अधिक नुकसान होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10 सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश देती है कि आवश्यकता पड़ने पर, वे ऐसे जब्ती और बचाव कार्यों में ऐसे व्यक्तियों के प्रतिरोध को रोकने में सहायता करें। इस प्रकार मवेशियों को जब्त करने वाले व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है। सहायता करने के लिए बाध्य पुलिस अधिकारी, सहायता प्रदान करने से पहले यह निर्धारित नहीं करेंगे कि मवेशियों की जब्ती वैध थी या नहीं। उन्हें जब्ती और बचाव कार्यों में जब्ती करने वाले व्यक्तियों के प्रतिरोध को रोकना होगा, यदि मवेशियों को जब्त करने वाले व्यक्ति उन्हें जब्ती या बचाव कार्यों में प्रतिरोध रोकने के लिए कहते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि मवेशियों की जब्ती, चाहे वह वैध हो या अवैध, हस्तक्षेप से सुरक्षित है। जिन व्यक्तियों के मवेशियों को अवैध रूप से जब्त किया गया है, उनके लिए उपाय अध्याय V के प्रावधानों में निहित हैं।

इन व्यावहारिक बातों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे व्यक्ति को, जिसने वास्तव में कोई नुकसान न पहुँचाया हो, अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कार्य करते हुए माना जाता है, ताकि अधिनियम द्वारा अधिकृत न की गई कोई भी कार्रवाई उसके विरुद्ध उसके गैर-कानूनी आचरण के लिए न की जाए। साथ ही, उन लोगों के हितों की रक्षा करना भी आवश्यक है जिनके मवेशियों को ज़ब्त किया गया है, भले ही उन्होंने फसल को कोई नुकसान न पहुँचाया हो। यह भी संभव है कि जिन व्यक्तियों को मवेशियों को ज़ब्त करने का अधिकार नहीं है, वे फसलों को नुकसान पहुँचा रहे लोगों के प्रति अपने व्यापक कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, फसलों को नुकसान पहुँचा रहे मवेशियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हों। ऐसे व्यक्ति भले ही नेक इरादे से ऐसा करें, लेकिन वास्तव में वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे होंगे और दीवानी न्यायालयों में हर्जाने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, या यदि मवेशियों को ज़ब्त करना दंड संहिता या किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपराध हो, तो आपराधिक रूप से भी उत्तरदायी हो सकते हैं। फसलों की रक्षा के लिए मवेशियों को ज़ब्त करने वाले व्यक्तियों और मवेशियों के मालिकों के हितों के बीच संतुलन बनाकर ही अध्याय V के ये प्रावधान बनाए गए प्रतीत होते हैं।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि अध्याय V के प्रावधान उन मामलों का व्यापक रूप से निपटारा करते हैं जिनमें अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए या इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पशुओं को जब्त किया गया हो, भले ही वह अधिनियम के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में न हो। अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित इन बातों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा पशुओं की अवैध जब्ती दंड संहिता के अंतर्गत चोरी का अपराध हो सकती है। दंड संहिता के प्रावधानों की गहन जांच करने पर भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

अब हम विचार करेंगे कि दंड संहिता के अंतर्गत चोरी का अपराध किन कृत्यों से बनता है। 'चोरी' को धारा 378 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> "जो कोई भी किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने के इरादे से उस संपत्ति को ले जाता है, वह चोरी का दोषी कहलाता है।"

इस न्यायालय को *के. एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य*[1] के मामले में चोरी के अपराध में क्या शामिल है, इस पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिला था। इसने पृष्ठ 630 पर कहा:

> "अतः, चोरी का अपराध (1) किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से हटाना, (2) संपत्ति को बेईमानी से लेने के इरादे से हटाना, इन दो बातों पर आधारित है। इस प्रकार, (1) हटाने के समय व्यक्ति की सहमति का अभाव, और (2) संपत्ति को हटाने के समय और उस समय बेईमानी का इरादा होना, चोरी के अपराध के आवश्यक तत्व हैं।"

पृष्ठ 631 में कहा गया है:

> "यह बात बिल्कुल सही है कि चोरी की परिभाषा के अनुसार संपत्ति को स्थानांतरित करना इस उद्देश्य से होना चाहिए, 'इस उद्देश्य' का अर्थ है 'बेईमानी से लेने का इरादा', इसलिए संपत्ति को बाहर ले जाना ही बेईमानी के इरादे से होना चाहिए।"

भारतीय दंड संहिता की धारा 23 और 24 के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा:

---

1 (1957) एस.सी.आर. 623.

"इन दोनों परिभाषाओं को एक साथ लेने पर, किसी व्यक्ति का बेईमानी का इरादा तब माना जा सकता है जब संपत्ति लेते समय उसका इरादा गैरकानूनी तरीकों से उस संपत्ति का लाभ उठाना हो जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, या गलत तरीकों से उस संपत्ति की हानि कराना हो जिसका वह कानूनी रूप से हकदार है। परिभाषा से यह भी स्पष्ट है कि अपेक्षित लाभ या हानि पूर्ण अधिग्रहण या पूर्ण वंचन होना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह पर्याप्त है यदि गलत तरीके से लाभ उठाने वाले व्यक्ति द्वारा संपत्ति को अस्थायी रूप से अपने पास रखा जाए या कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति से संपत्ति को अस्थायी रूप से दूर रखा जाए। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के दृष्टांत (1) में इसे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।"

न्यायालय ने इस दलील के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की कि दंड संहिता किसी विशेष परिणाम को उत्पन्न करने के इरादे और किसी विशेष परिणाम को उत्पन्न करने के ज्ञान या संभावना के बीच अंतर करती है और यह सिद्धांत कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के स्वाभाविक परिणाम का इरादा माना जाना चाहिए, एक कानूनी कल्पना है जिसे भारतीय दंड संहिता में दंडात्मक परिणामों के लिए मान्यता नहीं दी गई है।

जब तक संपत्ति को स्थानांतरित नहीं किया जाता, तब तक चोरी का कोई अपराध नहीं बनता, भले ही आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानी से संपत्ति को उसके कब्जे से छीनने का इरादा किया हो। भूमि पर अतिक्रमण करते पाए गए पशुओं को मात्र जब्त करना पशुओं को स्थानांतरित करने के बराबर नहीं है। पशुओं को स्थानांतरित करने की क्रिया उन्हें जब्त करने के बाद की होती है। अतः यह स्पष्ट है कि पशुओं को जब्त करना, यद्यपि अवैध है, चोरी का अपराध नहीं हो सकता।

पशुओं को जब्त करने के बाद, जब्त करने वाला व्यक्ति उन्हें पशु बाड़े में ले जाने के लिए उनका परिवहन करता है। पशु बाड़े में ले जाना ही अधिनियम द्वारा निर्देशित कार्य है,

धारा 10 में विशेष रूप से इसका उल्लेख है। बेशक, यह निर्देश भूमि या फसल को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जब्त किए गए पशुओं के संबंध में है, लेकिन यह निर्देश तब भी लागू माना जाएगा जब पशुओं को अधिनियम की धारा 10 के तहत जब्त करने के अधिकार का कथित रूप से प्रयोग करते हुए जब्त किया जाता है, विशेष रूप से जब धारा 20 में ऐसी जब्ती को अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया कार्य प्रथम दृष्टया बेईमानी का कार्य नहीं माना जा सकता है, और इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि पशुओं को पशु बाड़े में ले जाना चोरी का अपराध है।

किसी व्यक्ति को बेईमानी से किया गया कार्य तब कहा जाता है जब वह किसी एक व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुँचाने या किसी दूसरे व्यक्ति को अनुचित हानि पहुँचाने के इरादे से कोई कार्य करता है। मवेशियों की अवैध ज़ब्ती और उन्हें बाड़े में बंद करने के मामले में, मवेशियों को ज़ब्त करने वाले व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होता। वह केवल मवेशियों को बाड़े में ले जाता है। वह उनका उपयोग अपने उद्देश्य के लिए नहीं करता। वास्तव में, बाड़े तक ले जाने के दौरान मवेशियों पर उसका अधिकार केवल उनकी हिरासत में रहने तक ही सीमित रहता है। यह कहा जाता है कि इससे मवेशियों के मालिक को अनुचित हानि होती है क्योंकि उसे मवेशियों पर कब्ज़ा करने से रोका जाता है, मानो उसे कुछ समय के लिए संपत्ति से अनुचित रूप से वंचित कर दिया गया हो, हालाँकि यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति से वंचित होना स्थायी प्रकृति का हो। हमारा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में, मवेशियों के मालिक को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कहा जा सकता। मवेशियों को ज़ब्त करने वाला व्यक्ति इन तीन तरीकों में से किसी एक तरीके से कार्य कर सकता है: वह उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ परिस्थितियों में, ऐसा करने पर वह चोरी का दोषी हो सकता है। वह उन्हें खेत से बाहर निकालने के बाद खुला छोड़ सकता है। इस कार्रवाई से मवेशियों के दोबारा जमीन पर घुसपैठ करने का खतरा दूर नहीं होगा। वह उन्हें पशुशाला में ले जा सकता है।

ऐसा करने से वह न केवल अधिनियम के निर्देशों का पालन करता है, बल्कि स्वयं और पशु स्वामी दोनों के हित में भी कार्य करता है। वह स्वयं को और अधिक हानि से बचाता है और पशुओं को सुरक्षित हिरासत में रखकर तथा उन्हें किसी की भूमि या फसल को और अधिक नुकसान पहुँचाने से रोककर पशु स्वामी के हित की रक्षा करता है। पशु स्वामी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना और खर्चों का भुगतान करके पशु बाड़े से पशुओं को वापस ले सकता है। पशुओं को छुड़ाने के लिए उसे जो भी भुगतान करना पड़े, वह अधिनियम की धारा 20 के तहत उचित कार्रवाई करके उसकी भरपाई कर सकता है, क्योंकि उसकी शिकायत पर सुनवाई करने वाला दंडाधिकारी धारा 22 के तहत उसे हुए किसी भी नुकसान के मुआवजे के अतिरिक्त उसके द्वारा भुगतान किए गए जुर्माने और खर्चों के भुगतान का आदेश देने के लिए सशक्त है। इस प्रकार, अवैध रूप से जब्त किए गए पशुओं के स्वामी को न केवल जुर्माने और खर्चों की भरपाई की जाती है, बल्कि अवैध जब्ती के कारण हुए किसी भी नुकसान की भी भरपाई की जाती है। इसका अर्थ यह है कि अंततः अवैध रूप से जब्त किए गए पशुओं के स्वामी को कोई नुकसान नहीं होता है और इसलिए पशुओं की अवैध जब्ती से पशु स्वामी को कोई अनुचित हानि नहीं होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करने का दावा करते हुए पशुओं को जब्त करने वाला व्यक्ति पशु स्वामी को कोई अनुचित हानि नहीं पहुंचाता है।

मान भी लें कि मवेशियों को अवैध रूप से जब्त करने और बाड़े में रखने से मालिक को किसी प्रकार की अनुचित हानि हुई है, तो प्रश्न उठता है कि क्या खेत या फसल को नुकसान पहुँचाने के बहाने मवेशियों को बाड़े में ले जाने के उद्देश्य से खेत से अवैध रूप से जब्त करने वाले व्यक्ति पर बेईमानी से मवेशियों को जब्त करने का इरादा माना जा सकता है? मवेशियों को अवैध रूप से जब्त करने से मालिक को अनुचित हानि हुई होगी, लेकिन क्या उसका ऐसा इरादा था? हमारा मानना है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था। हालाँकि मवेशियों को जब्त करने का उसका अधिकार उसकी गलत धारणा पर आधारित था, फिर भी

उस समय उसका इरादा अधिनियम के अनुसार उन्हें बाड़े में ले जाना था ताकि भूमि या संपत्ति को और अधिक नुकसान न हो। यह सच है कि अभियोजित व्यक्ति का इरादा ज्यादातर उसके द्वारा किए गए कृत्य के परिणामों से ही पता चलता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी पूर्व तथ्य से यह निश्चित रूप से पता नहीं चल पाता कि किसी कृत्य को करने का इरादा क्या था। जब कोई व्यक्ति किसी कृत्य को खुले तौर पर अपने इरादे को व्यक्त करते हुए करता है, तो उसके इरादे को उसके कृत्य के परिणामों से जानने का कोई कारण नहीं दिखता, सिवाय उन मामलों के जहाँ यह पाया जाता है कि घोषित इरादा किसी अन्य वास्तविक इरादे का मात्र आवरण था, जिसे तब उसी तरह निर्धारित किया जाना चाहिए जैसे अव्यक्त इरादे के मामलों में किया जाता है।

उपरोक्त विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि जब कोई व्यक्ति अपने खेत में अतिक्रमण करने और फसल या उपज को नुकसान पहुँचाने के आरोप में मवेशियों को जब्त करता है और यह कहता है कि वह उन्हें पशुशाला ले जा रहा है, तो वह चोरी का अपराध नहीं करता, चाहे उसे उस खेत या फसल पर अपने अधिकार के बारे में कितनी भी गलतफहमी क्यों न हो। इस प्रकार जब्त किए गए मवेशियों के मालिक के पास अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्रवाई करने का उपाय है। उसे जब्त किए गए मवेशियों को छुड़ाने के लिए बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है।

अब हम संक्षेप में उन मामलों पर विचार कर सकते हैं जिनका उल्लेख इस तर्क के समर्थन में किया गया है कि मवेशियों की अवैध ज़ब्ती चोरी के बराबर है। ये मामले अधिनियम की धारा 10 के तहत शक्तियों के कथित प्रयोग में मवेशियों की ज़ब्ती और उन्हें बाड़े में बंद करने से संबंधित नहीं थे। ये मामले हैं: *क्वीन बनाम प्रेमनाथ बनर्जी*[2]; *वज़ुद्दी बनाम रहिमद्दी*[3]; *अब्दुल खालिक बनाम सम्राट*[4]; *परयाग राय बनाम अर्जू मियां*[5]; *क्वीन*

2 5 डब्ल्यू.आर. 68 (आपराधिक).

3 (1917) 18 क्रिल. एल.जे. 849.

4 ए.आई.आर. 1941 लाह. 221.

5 आई.एल.आर. 22 कैल. 139.

एम्प्रेस बनाम श्री चूर्ण चुंगो[6] । इन मामलों में मवेशियों की ज़ब्ती किसी भूमि या फसल को नुकसान पहुंचाने के कारण भी नहीं की गई थी। इन्हें व्यक्तियों द्वारा मालिकों के विरुद्ध अपने दावों को संतुष्ट करने या उन्हें किसी अन्य तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए ज़ब्त किया गया था। मवेशियों की ऐसी ज़ब्ती को 'चोरी' के बराबर माना गया है।

दूसरी ओर, ऐसे मामले भी हैं जिनमें यह माना गया है कि अवैध रूप से मवेशियों को जब्त करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई अपराध नहीं किया जाता है। *एम्प्रेस बनाम रामजियावान* [7] में यह माना गया कि अधिनियम के तहत मवेशियों की अवैध जब्ती दंड संहिता के तहत शरारत का अपराध नहीं है और मवेशियों के मालिक को धारा 20, 21 और 22 के प्रावधानों में उपाय मिल सकते हैं।

दयाल बनाम सम्राट[8] के मामले में, उन व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया गया जिन्होंने पशुओं के मालिकों द्वारा एक दिन पहले अपने पशुओं को उचित रूप से जब्त करने की कार्रवाई के प्रतिशोध में पशु बाड़े से पशुओं को जब्त कर लिया था, क्योंकि पशुओं को बाड़े में ले जाने से पशुओं की उपयोगिता या मूल्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई थी, और न ही उन्हें चोरी का दोषी ठहराया गया क्योंकि पशुओं के मालिकों को कोई अनुचित नुकसान नहीं हुआ था, भले ही उन्हें पशुओं को छुड़ाने के लिए खर्च उठाना पड़ता।

अतः हम मानते हैं कि इस मामले की परिस्थितियों में, रतन और अन्य अपीलकर्ताओं ने, जिन्होंने विवादित खेत से मवेशियों को जब्त किया था, चोरी का कोई अपराध नहीं किया, भले ही उन्हें उस खेत पर कोई अधिकार न हो, और इसलिए शमनारायण सिंह और अन्य, जो धारदार हथियारों और *लाठियों* से लैस होकर मवेशियों को छुड़ाने गए थे, रतन और अन्य के खिलाफ अपनी संपत्ति की रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं रखते थे।

---

6 आई.एल.आर. 22 कैल. 1017.

7 [1881] 1 ऑल. डब्ल्यू.एन. 158.

8 ए.आई.आर. 1943 अवध.280.

माननीय सत्र न्यायाधीश का मत था कि शमनारायण सिंह का दल ही हमलावर था। यह मत अनुचित नहीं कहा जा सकता, भले ही अभियोजन पक्ष के गवाहों ने सीधे तौर पर ऐसा न कहा हो। हालांकि, मामले की परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि सामान्यतः शमनारायण सिंह का दल ही हमलावर होता। रतन और अन्य लोगों के आचरण से वे ही व्यथित थे और अपने मवेशियों को बचाने के लिए जानबूझकर उनका पीछा किया था, और इसी आवेश में उन्होंने हमला शुरू किया होगा।

रतन के दल के चार व्यक्तियों को शमनारायण के दल के पांच व्यक्तियों की तुलना में अधिक चोटें आईं और गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या भी अधिक थी, यह तथ्य इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इन चार व्यक्तियों को कुल 26 चोटों में से 8 छिद्रयुक्त घाव और 4 चीरे वाले घाव लगे थे। शमनारायण के दल के पांच व्यक्तियों को 22 चोटें आईं, जिनमें केवल एक छेद वाला घाव (मृतक रामदेव को लगा एकमात्र घाव) और सुखारी महतो को लगे 4 चीरे वाले घाव शामिल थे।

भले ही शमनारायण सिंह का दल हमलावर न हो और हमला रतन के दल द्वारा शुरू किया गया हो, जैसा कि उच्च न्यायालय का राय प्रतीत होता है, फिर भी शमनारायण के दल को आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि रतन और अन्य लोग परिस्थितियों में यह आशंका कर सकते थे कि शमनारायण का दल शांतिपूर्ण नहीं है और मवेशियों को छुड़ाने के लिए उनके खिलाफ बल प्रयोग करेगा और संभावित बल प्रयोग से गंभीर चोटें आ सकती हैं। हमारा मत है कि रतन और अन्य अपीलकर्ताओं ने शमनारायण के दल के सदस्यों को चोट पहुंचाने और उस दल में शामिल रामदेव की मृत्यु का कारण बनने में कोई अपराध नहीं किया है। तदनुसार, हम अपील स्वीकार करते हैं, रतन अहीर को भारतीय को दंड संहिता की धारा 302 के तहत और अन्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत दोषसिद्धि और उन अन्य अपराधों के लिए भी दोषसिद्धि अपास्त करते हैं जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। उन्हें तत्काल हिरासत से रिहा किया जाएगा।

अपील स्वीकृत किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।